RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

63 वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, शुक्रवार 18 जून 2021 ■ वर्ष 63 ■ अंक 139 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

योगगुरू बाबा रामदेव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

रायपुर, 17 जून । पूरी दुनिया में योग का लोहा मनवा चुके बाबा रामदेव की मुश्किले कम नहीं होती दिख रही है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। यहां बाबा रामदेव का पुरा नाम योग गुरु राम कृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ मड्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है. सिविल लाइन थाना में बाबा रामदेव के खिलाफधारा विभिन्न धाराओं के तहत 186, 188, 269, 270, 504, 505 (1), 51, 52, 54 मामला दर्ज किया गया है।

एक्स-एनकाउंटर विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा के घर छापा

मुंबई ,17 जून (ए)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एसयूवी प्लांटिंग और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में अंधेरी में पूर्व मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा। एनआईए की एक टीम ने उनके घर पर छापा मारा और तलाशी ली और बाद में शर्मा को हिरासत में लिया। एनआईए ने यह कार्रवाई 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास 20 जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरे नोट के साथ एसयूवी के सनसनीखेज मामले में की है।

जुलाई में आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली ,17 जून (ए)। देश में अभी 18 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब उम्मीद बढ़ी है कि अगले कुछ महीनों में बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी और उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा।

सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई में कोरोना की वैक्सीन नोवावैक्स का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। अमेरिकी बायोटेक्नॉलजी कंपनी नोवावैक्स ने पिछले साल सितंबर में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन बनवाने का समझौता किया था।

12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुको

10वी, 11वीं और 12वीं के अंकों पर आएगा रिजल्ट

नई दिल्ली ,17 जून (ए)। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला वापस नहीं होगा और इसके साथ ही सीआईएससीई और सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को मंजूरी दे दी जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर क्रमशः 30:30:40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा।

काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशंस (सीआईएससीई) ने हालांकि कहा कि वह विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए पिछले छह कक्षाओं के प्रदर्शन पर विचार कर रहा है जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 12वीं के विद्यार्थियों के अंतिम नतीजों को तैयार करने के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रदर्शन को आधार बनाने का प्रस्ताव किया है। दोनों बोर्ड ने कहा कि वे 31 जुलाई या उससे पहले नतीजे घोषित करेंगे। सीबीएसई ने अदालत को अपनी मूल्यांकन प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 12वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन में 30 प्रतिशत अंक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के आधार पर, 30 प्रतिशत 11वीं कक्षा के अंक के आधार पर और 40 प्रतिशत अंक 12वीं कक्षा की छमाही परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।

सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक आधार पर प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में मिले अंक जिसे स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया गया है उसपर भी अंतिम नतीजे तैयार करते वक्त गौर किया जाएगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की विशेष अवकाश पीठ ने इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि सीबीएसई और सीआईएससीई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। सिंह का तर्क था कि समान विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) पारंपरिक तरीके से कराया जाएगा।

पीठ ने कहा कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले को आगे नहीं ले जाया जाना चाहिए। हमने पहले ही सैद्धांतिक रूप बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले को स्वीकार किया है और जिसे हमारे सामने रखा गया था। वैसे भी जो विद्यार्थी अंकों में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं यह व्यस्था ऐसे विद्यार्थियों का ख्याल रखती है। दूसरे शब्दों में कहें, तो जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनको लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगी। वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मूल्यांकन योजना को स्वीकार करने को लेकर कोई आशंका नहीं है और बोर्ड इस पर आगे बढ़ सकते हैं। पीठ ने सीबीएसई की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सीआईएससीई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जेके दास से कहा कि हालांकि, (मूल्यांकन) योजना में विवाद समाधान का प्रावधान उस स्थिति में होना चाहिए अगर विद्यार्थी अंतिम नतीजे में सुधार चाहते हैं और दूसरा नतीजे घोषित होने और वैकल्पिक परीक्षा के लिए समय सारिणी जारी होती है। दोनों बोर्ड ने पीठ के सुझाव पर सहमति जताई और इस मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है, उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह मूल्यांकन योजना पर अपना पक्ष रखेंगे।

आधुनिक होंगी देश की 41 आयुध फैक्टरियां

केंद्र ने दी 7 कंपनियों में बदलाव को मंजूरी

नई दिल्ली ,17 जून (ए)। केंद्र सरकार ने एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाते हुए बुधवार को करीब 200 साल पुराने आयुध कारखाना बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार करना है। इसके लिए बोर्ड के तहत संचालित हथियार और असलहा तैयार करने वाली 41 आयुध फैक्टरियों को आपस में विलय करते हुए सात कंपनियों में तब्दील किया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने करीब दो दशकों से लंबित इस सुधार प्रक्रिया पर मंजूरी देकर मुहर लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इन आयुध कारखानों में कार्यरत 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह निर्णय देश के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है। यह एक बड़ा फैसला है और इससे देश की रक्षा जरूरतों को पूरी की जा सकेंगी। इससे हमें अपने रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, सभी सात कंपनियां रक्षा क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह ही होंगी और उनका संचालन पेशेवर प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जिनका लक्ष्य उत्पादों की संख्या बढ़ाने के साथ ही किफायती और बेहतरीन गुणवत्ता देना होगा। सुधार की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत की जा रही है। एक अधिकारी अनुसार, विलय के बाद बनने वाली सात कंपनियों में गोलाबारूद रूप, ब्लीकल रूप, हथियार और उपकरण रूप के साथ ही टुकड़ियों की सुविधाओं की सामग्री व अन्य रूप होंगे। कैबिनेट के इस फैसले से इन कंपनियों को स्वायत्तता के साथ-साथ क्षमताओं के विकास और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पुरानी खामियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

केन्द्र सरकार ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड के विलय का निर्णय तो लिया, लेकिन इसके साथ-साथ इसके कर्मचारियों आदि के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समूह ए, बी और सी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्मचारियों के पेंशन और अन्य भत्ते का वहन केन्द्र सरकार करेगी। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आगले दो साल तक उत्पादन इकाई से जुड़े समूह ए,बी और सी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बिना कोई बदलाव किए इन्हें प्रतिस्थापना के आधार पर बनने वाली सात कारपोरेट कंपनियों में स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का आधिकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रियों के समूह को दे दिया है। ताकि वह आयुध निर्माण समेत अन्य क्षेत्र में प्रोफेशनल क्षमता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण पहल सुनिश्चित की जा सके।

राजधानी रायपुर में शीघ्र खुलेगा वैद्य अस्पताल

- औषधीय पौधों की खेती-किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण : वन मंत्री
- औषधीय पौधों का कृषिकरण व छत्तीसगढ़ में संभावनाएं विषय पर वेबिनार

रायपुर, 17 जून । वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर आज छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा आयोजित वेबिनार में वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने वेबिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने यहां राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों के कृषिकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की और इसे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने की। वेबिनार में 130 से अधिक कृषक, भू-स्वामी, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी तथा गृहणी इससे जुड़कर लाभ उठाया।

वन मंत्री अकबर ने आगे कहा कि राज्य में औषधीय पौधों की खेती से अन्य फसलों की तुलना में किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होगी। इससे राज्य में गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों का उत्पादन भी बढ़ेगा। इस तारतम्य में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत इस वर्ष धान के फसल हेतु इनपुट सब्सिडी 9000 रूपए प्रति एकड़ व धान के स्थान पर अन्य फसलों को लगाए जाने हेतु 10000 रूपए प्रति एकड़ तथा वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु तीन वर्ष हेतु प्रति वर्ष 10000 रूपए इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में धान के अतिरिक्त अन्य फसलों में औषधीय पौधों के रोपण हेतु लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने बोर्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान लगभग एक करोड़ औषधीय पौधों को तैयार कर वितरण के लक्ष्य निर्धारित करने पर खुशी जाहिर किया।

इस अवसर पर राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पौधों के लिए बहुत उपयुक्त है। बोर्ड द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री अकबर के दिशा-निर्देशन में औषधीय पौधों के विस्तार और परंपरागत वैद्य चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

फरीदाबाद में 10 हजार मकानों पर चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली ,17 जून (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित करीब 10 हजार घरों को छह हफ्ते के भीतर ढहाने का अपने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

पीठ ने कहा कि हमारी राय में इस चरण पर न्यायालय द्वारा दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में ढहाने की कार्रवाई न की जाए। वहां अधिकतर प्रवासी मजदूर रहते है और संकट के इस दौर में वे बेघर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निगम, पुनर्वास योजना के लिए यहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। जवाब में पीठ ने कहा कि ढहाने की कार्यवाही को हम नहीं रोक सकते। लोगों के पास वन भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर था। पिछले छह सालों से यह सब कुछ चल रहा है। वही पुनर्वास योजना के लिए दस्तावेजों को स्वीकार न करने के आरोप पर पीठ ने निगम को इस पर नियम के तहत काम करने के लिए कहा है। वकील भट्ट ने कहा कि महामारी के दौरान बेदखल किए जाने वाले लोगों के लिए कम से कम एक अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं हैं। जवाब में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को देखना हरियाणा राज्य का काम है।

एंटीलिया विस्फोटक मामले में तीन साजिशकर्ता गिरफ्तार

नयी दिल्ली 17 जून (ए)। राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई में कामाइकल रोड पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के समीप विस्फोटकों से लदे वाहन की बरामदगी के मामले में तीन साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

एनआईए के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सतीश तिरुपति मोठकुरी उर्फ ??तत्री भाई, मनीष वर्सत सोनी और पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा शामिल हैं। इन तीनों को आज एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया , जहां से उन्हें 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

एनआईए इस मामले में सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एनकाउंटर विशेषज्ञ के तौर पर पहचाने जाने वाले प्रदीप शर्मा से एनआईए अधिकारी पूर्व में भी दो बार पूछताछ कर चुके हैं। वह मुंबई पुलिस के पूर्व सिपाही सचिन वाजे के करीबी के रूप में जाना जाता है, जिसे केंद्रीय एजेंसी ने कारमाइकल रोड पर विस्फोटक से लदे वाहन की बरामदगी और मनसुख हिरेन की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है, जिसके वाहन का इस्तेमाल साजिशकर्ताओं द्वारा विस्फोटक रखने के लिए किया गया था।

आज का इतिहास

1993 तुरथा परिषद ने बोलनिया के छह शहरों के लिए शांति सैनिकों को मंजूरी दी।

2000 राजधानी दिल्ली में लालकिले के पास दो बम विस्फोटों में 2 मरे व 11 अन्य घायल।

2001 मणिपुर में पुलिस फायरिंग के कारण 13 लोग मरे।

2003 कनाडा में समलिंगी जोड़े को विवाह करने की अनुमति दी।

बहुत खूब

कुम के दौरान हुआ देश का सबसे बड़ा कोविड टेस्ट घोटाला

आपदा को उन्होंने अवसर में बदल दिया!

स्टेरॉयड ने नींद में भी डाला खलल, कोरोना होने के बाद अनिद्रा के शिकार हो रहे लोग

भोपाल, 17 जून (ए)। कोरोना से ठीक होने के बाद लोग अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह स्टेरॉयड है। इसका असर नींद को नियंत्रित करने वाले हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस पर होता है। दरअसल, कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों को स्टेरॉयड बाहर से इंजेक्शन या टैबलेट के तौर पर दिया गया है। इससे शरीर में प्राकृतिक रूप से स्टेरॉयड का बनना ढेढ़ से दो महीने के लिए बंद हो जाता है। इसकी कमी से मेलाटोनिन हार्मोन भी नहीं बनता जो नींद लाने के लिए जरूरी है।

उधर, स्टेरॉयड नहीं बनने और तनाव की वजह से अनिद्रा के लिए जिम्मेदार कार्टीसोल्स हार्मोन ज्यादा बनते हैं। राजधानी के सभी मनोचिकित्सकों के यहां मिलाकर हर दिन 50 से 60 मरीज अनिद्रा वाले पहुंच रहे हैं। यह सभी कोरोना से हाल ही में ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या हो रही है उसमें स्टेरॉयड का ज्यादा उपयोग, एंग्जायटी डिसऑर्डर, घबराहट की समस्या है।

बंसल अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी ने कहा कि अनिद्रा की शिकायत उन्हें ज्यादा हो रही है जो आइसीयू में भर्ती रहे। इसके अलावा उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जिन्हें लंबे समय तक स्टेरॉयड दिया गया है। उन्होंने बताया कि आइसीयू में रहने के बाद दिन-रात का फर्क पता नहीं चलता। इस वजह से नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन के उत्सर्जन का चक्र प्रभावित हो जाता है।

डॉ. सत्यकांत ने बताया कि अनिद्रा के शिकार लोगों में वे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं जिन्होंने स्वजन को खोया है और खुद कोरोना से प्रभावित हुए हैं।

कोरोना वायरस के सभी वैरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी 2-डीजी

- डीआरडीओ की दवा 2-डीजी पर अध्ययन में किया दावा

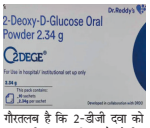

नई दिल्ली ,17 जून (ए)। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित कोरोना वायरस की दवा 2-डियोक्सी-डी-ग्लुकोज (2-डीजी), कोविड-19 के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रभावी है और यहां तक कि यह दवा सार्स-सीओवी-2 वायरस के म्यूटीप्लिकेशन को भी कम करती है।

प्रारंभिक अध्ययन से यह भी पता चला है कि डीआरडीओ की एंटी-कोविड दवा कोशिकाओं में संक्रमण से प्रेरित साइटोपैथिक प्रभाव (सीपीई) को कम करती है और उन्हें खत्म होने से बचाती है। गौरतलब है कि 2-डीजी दवा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में 17 मई को लॉन्च किया था। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा की पहली खेप जारी करते हुए केंद्र सरकार ने दावा किया कि इस दवा में मरीज के ठीक होने में लगने वाले औसत समय को ढाई दिन और ऑक्सीजन की मांग को 40 फीसदी तक कम करने की क्षमता है। इसे भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा एक जून को मध्यम से गंभीर कोरोना वायरस मरीजों के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया था।

नहीं हुई अध्ययन की समीक्षा

गत 15 जून को प्रकाशित इस नए अध्ययन की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। इस अध्ययन रिपोर्ट को अनंत नारायण भट्ट, अभिषेक कुमार, योगेश राय, धिविया वेदगिरि और अन्य ने तैयार किया है। अध्ययन में डीआरडीओ की एंटी-कोविड दवा 2-डीजी का उपयोग बीमारी से पीड़ित रोगियों में कोविड -19 संक्रमण से प्रेरित मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग को लक्षित करने और बाधित करने के लिए किया गया था। परिणामों से पता चला कि कोविड-19 संक्रमण शरीर में ग्लूकोज और कोशिकाओं में ग्लाइकोलाइसिस के उच्च प्रवाह का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप फ्लोरोसेंट ग्लूकोज / 2-डीजी एनालॉग और 2-एनबीडीजी का चयनात्मक तरीके से उच्च संचय होता है।

कोरोना से दैनिक मौतों में आई गिरावट

नई दिल्ली ,17 जून (ए)। देश में पिछले दो दिन से कोरोना वायरस के दैनिक मामलो में मामूली ही सही, लेकिन बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है। वहीं देश में पिछले 71 दिनों बाद सक्रीय मामलों की संख्या सबसे कम देखी गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 67208 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,97,00,313 पर पहुंच गई। जबकि कोरोना के कारण पिछले एक दिन में 2,330 लोगों की जान चली गई। इस प्रकार देश में कोरोना से अपनी जवान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3,81,903 हो गई है। वहीं अस्पतालों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों की संख्या कम होकर 8,26,740 रह गई है।